देहरादून (उत्तराखण्ड)
बृहस्पतिवार 16.04.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रदेशभर में 50 'स्विफ्ट स्कूल' स्थापित किये जायेंगे, विद्यालयी शिक्षा विभाग ने एमओयू साइन किया।
- सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के छात्रों ने विकसित किया 'विधि सहयोगी' मोबाइल एप, लोगों को कानूनी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएगा यह एप।
- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वॉटर बेल बजाने के निर्देश दिए।
- कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में मखाना रोपण कर मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की।

स्विफ्ट स्कूलों का होगा शुभारंभ

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में 50 'स्विफ्ट स्कूल' स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये शिक्षा विभाग और कॉन्वजीनियस फाउण्डेशन के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। जिसके तहत इन विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये आधुनिक तकनीक युक्त डिजिटल अवसंरचना विकसित की जायेगी। साथ ही फाण्डेशन छात्र–छात्राओं को 1000 लैपटॉप भी वितरित करेगी। स्विफ्ट स्कूलों की स्थापना के लिये विभाग ने स्कूलों का चयन कर लिया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को तकनीकी आधारित बनाने के लिये निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में समग्र शिक्षा और कॉन्वजीनियस फाउण्डेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। इसके तहत प्रदेशभर में 50 'स्विफ्ट स्कूल' की स्थापना की जायेगी, पौड़ी और चम्पावत के 19–19 तथा देहरादून और हरिद्वार जिले में 6–6 विद्यालय इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। डॉ. रावत ने बताया कि 'स्विफ्ट स्कूल' एक एकीकृत विद्यालय परिवर्तन मॉडल है। जिसमें व्यक्तिगत शिक्षण, कक्षाओं में आधुनिक तकनीक का उपयोग, शिक्षकों को डेटा आधारित सहायता के साथ ही डिजिटल अवसंरचना का समावेश होगा। जिससे छात्र–छात्राओं को उनके सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षा देने में मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षकों को डेटा आधारित जानकारी मिलेगी जिससे वह कक्षा में अधिक प्रभावी अध्यापन कर सकेंगे। स्विफ्ट स्कूलों में तकनीकी के माध्यम से बच्चों के सीखने की कमियों की समय पर पहचान कर उन्हें आवश्यक शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी।

चारधाम यात्रा तैयारी

राज्य में चारधाम यात्रा की शुरूआत 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन हो रही है। देहरादून जिले में यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने ट्रांजिस्ट कैम्प ऋषिकेश में संबधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा ट्रांजिस्ट कैंप में पंजीकरण कक्ष एवं परिसर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में 24 काउंटर और आईएसबीटी पर 6 पंजीकरण काउंटर लगाए गए हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि पंजीकरण के लिए 30 मोबाइल टीम में लगाई गई हैं, जिनमें 25 टीमें दिन में तथा 5 टीम रात्रि से प्रातः तड़के तक लोगों का पंजीकरण करेंगी। ऋषिकेश एवं हरबर्टपुर यात्रा पड़ाव के लिए 6 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। जिनमें 3 टीमें ऋषिकेश और 3 टीमें हरबर्टपुर में तैनात रहेंगी।

विधि सहयोगी एप

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के छात्रों ने आम लोगों को कानूनी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'विधि सहयोगी' मोबाइल एप विकसित किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने देहरादून स्थित लोकभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह के समक्ष इस एप का प्रस्तुतिकरण दिया।

कुलपति ने बताया कि 'विधि सहयोगी' एक एआई सक्षम मोबाइल एप है। यह लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और विधिक सहायता तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस एप के माध्यम से उपयोगकर्ता कानूनी विषयों की जानकारी प्राप्त करने के अलावा आवश्यकता पड़ने पर अधिवक्ताओं से संपर्क भी कर सकेंगे। भविष्य में इसमें ऑनलाइन परामर्श, केस ट्रैकिंग, दस्तावेज प्रबंधन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। कुलपति ने बताया कि इस पर कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एप को तैयार करने वाली टीम और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवाचार समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वॉटर बेल बजाने के निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वॉटर बेल बजाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थी गर्मियों के मौसम में नियमित अंतराल पर पानी पी सकें। ग्रीष्मकाल में हीट वेव की तैयारियों को लेकर सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने, कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन, ओआरएस एवं आवश्यक दवाओं का भंडारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि विद्यार्थियों को हीट वेव से बचाव सम्बन्धी व्यवहारिक जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में बढ़ते तापमान एवं संभावित हीट वेव

की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को गर्मियों के मौसम में जिन भी क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो, वहां सभी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।

मखाना की खेती

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में मखाना रोपण कर मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि देश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड उत्तराखंड सहित देश के 11 राज्यों में मखाना उद्योग को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2025–26 के अंतिम त्रैमास में उत्तराखंड को 50 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर स्थित कृषि केंद्रों के सहयोग से किसानों को मखाना उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

हेल्थ अलर्ट अभियान

चारधाम यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ अलर्ट अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले ही जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और संभावित जोखिमों को कम करना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में विशेष रूप से उन दिक्कतों को लेकर जागरूक किया जा रहा है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सामने आती हैं। इनमें सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी, थकान, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और अचानक मौसम बदलने से होने वाली परेशानियां शामिल हैं। विभाग का मानना है कि यदि यात्री पहले से स्वास्थ्य जांच करा लें और जरूरी सावधानियों का पालन करें, तो यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकती है। जिन राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं, वहां स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है।

नारी सशक्तिकरण

नारी सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड में एक बड़ी पहल सामने आई है। प्रदेश की महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इसके तहत महिलाओं से 9667173333 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, "मैं उत्तराखंड की समस्त मातृशक्ति से निवेदन करती हूं कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ें और मिस्ड कॉल देकर अपने समर्थन को दर्ज कराएं।